वर्ष: 23 अंक: 114

नोएडा (गौतमबुद्धनगर) शुक्रवार
13 सितम्बर 2019
मूल्य: 1.00 रुपया
आर.एन.आई. नं. 72344/98
E-maill: vartmansatta@ yahoo.com

वर्तमान सत्ता

एनसीआर का प्रमुख दैनिक

प्रिय पाठको
अब से आप दैनिक वर्तमान सत्ता गौतमबुद्धनगर की ताजा न्यूज देख सकते हैं
www.facebook.com\dainikvartmansatta पर
आपके आसपास की अपडेट जानकारी देखें व हमसे जुड़ें धन्यवाद।

23 देशें के खिलाड़ी पहुंचे

ग्रेटर नोएडा में हो रहा है चौंपियनशिप का आयोजन

विशेष प्रतिनिधि

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा। शहर के विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कांप्लेक्स में आज से एशियन सैंबो चौंपियनशिप–2019 का आगाज होगा। तीन दिवसीय चौंपियनशिप में भारत समेत 23 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। सैंबो फेडरेशन ऑफ इंडिया यह आयोजन कर रहा है। बुधवार को खिलाड़ी ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। प्रतियोगिता में अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, कजाकिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया, तजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, यमन, सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कोरिया, थाईलैंड समेत अन्य देश शामिल हैं। वहीं, पाकिस्तान इस चौंपियनशिप में भाग नहीं ले रहा है।

चौंपियनशिप का आयोजन स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के इंडोर स्टेडियम में होगा। सैंबो खेल को भारत में आए 25 साल पूरे हो गए हैं। भारत में पहली बार ये चौंपियनशिप हो रही है। जूनियर, सीनियर और यूथ के अलग–अलग भार वर्ग में मुकाबले खेले जाएंगे। सुबह दस बजे से मुकाबले शुरू होंगे और शाम को साढ़े छह बजे तक चलेंगे। उसके बाद पुरस्कार वितरण समारोह होगा। 13, 14 और 15 सितंबर तक यह चौंपियनशिप चलेगी। एक देश के दल में अधिक से अधिक 76 सदस्य होंगे। इनमें 67 खिलाड़ी, दो रेफरी, छह कोच शामिल होंगे। भारत की तरफ से भी बड़ी संख्या में खिलाड़ी चौंपियनशिप में भाग ले रहे हैं।

चौंपियनशिप में चमकेगा सूरज

ग्रेटर नोएडा में एशियन सैंबो फेडरेशन के निर्देश पर एशियन सैंबो चौंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में शहर के खिलाड़ी सूरज सिंह का 57 भार वर्ग में भी चयन हुआ है और वह देश के लिए पदक की दावेदारी प्रस्तुत करेंगे।

नवीन नगर निवासी सूरज सिंह केजीके कालेज में बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र हैं। सूरज ने बताया कि उन्होंने छह साल पहले जूडो खेलना शुरू किया था। गत वर्ष आल इंडिया यूनिवर्सिटी अमृतसर में खेलने गए थे। वर्ष 2018 में ही पटना में हुई नेशनल सैंबो गोल्ड मेडल मिला था। वह एक साल पहले क्रीड़ा अधिकारी अनिमेष सक्सेना के निर्देशन में अभ्यास कर रहे हैं। जून में कुरांश की एशियन चौंपियनशिप थाईलैंड गए थे। उन्होंने बताया कि आर्थिक तंगी की वजह से समस्या होती है। थाईलैंड जाने के लिए क्रीड़ा अधिकारी ने मदद की थी। अब वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतकर नाम रोशन करना चाहते हैं।

पूरे देश में 1 सितम्बर को मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद जहां पुलिस लोगों के दबादब चालान काट रही है, वहीं दूसरी और पुलिसकर्मी इस नियम की खूब धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस का नजारा आप उक्त चित्र में देख रहे हैं।

चौकी इंचार्ज से दोगुनी रिश्वत व उसे हटाने के आश्वासन पर धरना समाप्त

गौतमबुद्धनगर। जिले की जेवर कोतवाली के एक दारोगा पर अवैध उगाही का आरोप व अघोषित बिजली कटौती को लेकर भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के तत्वावधान में क्षेत्र के दर्जनों गांवों के किसानों व ग्रामीणों ने कोतवाली का घेराव किया। लोगों ने कोतवाली प्रभारी से दारोगा द्वारा अवैध रूप से की गई वसूली को जुर्माना समेत दोगुना लौटाने की मांग करते हुए परिसर में ध रना दिया। किसान अघोषित बिजली कटौती को लेकर विभागीय अधिकारियों व आरोपित दारोगा को धरने में बुलाने की मांग पर अड़े थे। एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर किसानों से वार्ता की और दारोगा को चौकी से हटाने व एक दो दिन के अंदर बिजली आपूर्ति सुचारु कराने का आश्वासन दिया तो किसानों ने धरना समाप्त कर दिया।

किसान नेता महेंद्र सिंह चौरोली के नेतृत्व में दर्जनों गांवों के सैकड़ों महिला पुरुष जेवर कोतवाली पहुंचे। लोगों का आरोप था कि नीमका पुलिस चौकी प्रभारी ने एक व्यक्ति को डरा धमकाकर एक मुकदमे से उनका नाम हटाने के लिए चौदह हजार रुपये मांगे। धरनास्थल पहुंचे कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अजय कुमार अग्रवाल से किसानों ने दारोगा को मौके पर बुलाने की मांग की।

कोतवाली प्रभारी के बार–बार फोन करने के बाद भी दारोगा कोतवाली नहीं पहुंचा तो लोगों ने 14 हजार रुपये के बदले जुर्माना समेत 28 हजार रुपये वापस दिलाने की मांग की। उपजिलाधिकारी विजय शंकर मिश्र ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण दारोगा को बुलाने की मांग कर रहे थे। बाद में कोतवाली प्रभारी ने दारोगा को चौकी से हटाने व दारोगा के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया तो किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। धरने पर सतीश चौधरी, राकेश अत्री, शमशाद सैफी, बिजेंद्र, सचिन जैन, ठाकुर प्रेमवीर, प्रकाश फौजी, चेतराम सिंह, राजीव प्रधान, नरेश पंडित आदि मौजूद रहे।

जिला भाजपा का मुख्यालय होगा अंसल गोल्फ लिंक

ग्रेटर नोएडा। भाजपा ने जिला कार्यालय के लिए अंसल गोल्फ सोसाइटी तिलपता में जिला कार्यालय के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया. जिसमें मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जी उपस्थित रहे. भूमि पूजन का कार्यक्रम शुभ मुहूर्त 4रू35 पर आरंभ हुआ जिसमें वेद मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ करके नींव रखने का कार्य संपन्न आरंभ किया।

भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनपद गौतम बुध नगर कार्यालय का भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया है जिससे अब भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक निश्चित स्थान रहेगा. भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि संगठन विस्तार के लिए बूथ संगठन विस्तार के कार्य बूथ अध्यक्ष कार्यकारिणी 18 से 22 सितंबर में होने वाले के कार्य में जुट जाएं। कार्यकर्ताओं के बल पर उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन पर्व संगठन सदस्यता कार्यक्रम सफल रहा आज पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक 18 करोड़ से अधिक सदस्य बने हैं. भूमि पूजन के अवसर पर मुख्य रूप से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जिला अध्यक्ष विजय भाटी क्षेत्रीय मंत्री ठाकुर हरीश सिंह वरिष्ठ नेता विजेंद्र भाटी सुभाष भाटी दादरी चेयरमैन गीता पंडित इंदर नागर कर्मवीर आर्य जग भूषण गर्ग सत्यपाल शर्मा डॉ अशोक नागर वेद प्रकाश गुप्ता बिना शुक्ला अनु पंडित राकेश राणा लक्ष्मण सिंगल ओमबीर बैसला सतीश गुलिया संजय राणा संजय भाटी चंद्रमणि भारद्वाज राजा रावल मुकेश नागर संतराम भाटी विजय रावल गजेंद्र मावी रवि जिंदल महेश शर्मा सुशील शर्मा नीरज शर्मा आनंद भाटी सुखबीर आर्य बीएस नागर उषा वत्स अनीता गौतम राजबाला अजीत मुखिया राजेंद्र शर्मा देवेंद्र कसाना मोनू गर्ग पंकज रावल आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

जेल में ऐसे पहुँचाया जाता था नशीला पदार्थ

ग्रेटर नोएडा। यहाँ की सूरजपुर पुलिस ने दो ऐसे शातिर नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है जो अपना माल जेल तक पहुँचाने में कोर्ट में जेल से पेशी पर आए कैदी के माध्यम से जेल पहुंचाते थे. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को सूरजपुर कोर्ट परिसर से गिरफ्तार किया है. इनसे कैप्सूल, नशे की गोलियां, गांजा, बी.कॉम कंपनी के कैप्सूल, चरस के कैप्सूल के पैकेट बरामद किया है. तीनो उस समय पकड़े गए जब सूरजपुर पुलिस ने कोर्ट के अंदर चेकिंग अभियान चलाया. इसी दौरान तीन उन्हें तीन संदिग्ध व्यक्ति परवेज निवासी सेक्टर 49 ,राहिल निवासी दनकौर और संतोष निवासी गाजियाबाद मिल गए।

एसपी देहात कुमार रणविजय सिंह ने बताया ये चलते चलते कोर्ट परिसर में जेल से पेशी पर आए कैदियों को पैकेट पकड़ा देते थे. उसमे गांजा का कैप्सूल होता जो कैदी मुंह में निगल लेते थे. अगले दिन शौच में वो बाहर आ जाता था. चूँकि गांजा कैप्सूल पॉलिथीन कवर में अच्छे से पैक रहता था उसका कुछ नहीं बिगड़ता था. सप्लायर कैदियों को यह कैप्सूल 400–500 रूपये में बेचते थे जो जेल में जाकर 1000 रूपये तक में बिकता था. पुलिस ने तीनों सप्लायर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है।

इलेक्ट्रॉनिक सिटी को 2500 एकड़ जमीन

जेवर एयरपोर्ट के निकट लाखों को मिलेगा रोजगार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत एनसीआर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी। इससे चार लाख युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए नीति बनाई जा रही है। इससे विदेशी कंपनियों को यहां अपना उद्यम स्थापित करने में न सिर्फ आसानी होगी बल्कि उन्हें रियायतें भी दी जाएंगी। निर्माण के लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। एनसीआर में 2500 एकड़ में इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थापित की जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने से यहां आवागमन भी सुगम होगा। दरअसल देश में मोबाइल फोन, एलसीडी व एलईडी टेलीविजन व एलईडी के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ी है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। बीते पांच वर्षो में विदेशी कंपनियों की 123 इकाइयां यहां स्थापित हुईं। यूपी ने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में उल्लेखनीय गति दी है। भारत में होने वाले कुल मोबाइल निर्माण का 45 प्रतिशत निर्माण यूपी में हो रहा है। देश की 38 मोबाइल निर्माता कंपनियों में से करीब 13 कंपनियां अकेले यूपी के नो उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा का कहना है कि एनसीआर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना जल्द की जाएगी। इसके लिए जमीन तलाशने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के तहत उद्यमियों को अपना उद्योग लगाने में यहां रियायतें दी जाएंगी।

मैनेजर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया

दनकौर। दनकौर कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला ने गांव के एक युवक व उसके दोस्त पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए दनकौर कोतवाली में तहरीर दी है। क्षेत्र में रहने वाला एक युवक एक मोबाइल कंपनी में कार्यरत है। आरोप है युवक ने गांव की एक महिला से मोबाइल कंपनी में मैनेजर बनाने की बात कहते हुए दो लाख रुपये की मांग की। महिला ने पति से दो लाख रुपये लेकर आरोपित को दे दिए, लेकिन आरोपित दस दिन तक पीड़िता को बहकाता रहा। आरोप है कि युवक ने पीड़िता को झांसे में लेकर करीब 13 तोला सोना और कुछ चांदी के जेवरात भी ले लिए। 24 अगस्त को आरोपित ने महिला को इंटरव्यू देने के लिए ग्रेटर नोएडा बुला लिया। महिला ने बताया कि आरोपित उसे एक कमरे में ले गया जहां आरोपित ने अपने एक दोस्त के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

सुरेन्द्र नागर का निर्विरोध राज्यसभा में जाना तय

ग्रेटर नोएडा। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता लेने वाले पूर्व सांसद सुरेंद्र नागर को बीजेपी ने राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित किया था। बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ सुरेंद्र नागर ने बृहस्पतिवार को लखनऊ में नामांकन दाखिल किया। अभी तक दूसरी पार्टी से मैदान में कोई प्रत्याशी न आने से उनका निर्विरोध ा चुना जाना तय हो गया है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जरों के कद्दावर नेता सुरेंद्र नागर ने 2009 में गौतमबुद्ध नगर सीट से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने के बाद वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। बाद में सपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा। सुरेंद्र नागर ने कुछ दिन पहले भाजपा का दामन थाम लिया था। दामन थामने के लगभग एक माह के अंदर ही पार्टी ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं व समर्थकों की भारी भीड़ के साथ सुरेंद्र ने नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन में गौतमबुद्ध नगर से दादरी विधायक तेजपाल नागर, जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह के अलावा गाजियाबाद, बुलंदशहर व सहित अन्य जिलों से नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। लोगों ने माला पहनाकर उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर सिकंद्राबाद विधायक विमला सोलंकी, खुर्जा विधायक बिजेंद्र सिंह, डा. वीएस चौहान, योगेंद्र चौधरी, महेश अवाना, प्रधान श्रीनिवास आर्य, प्रमोद भाटी सहित अन्य लोग मौजूद थे। रिटर्निंग अफसर ब्रजभूषण दुबे ने बताया कि उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की जांच 13 सितंबर को तथा 16 सितंबर को नाम वापसी हो सकेगी।

किसानों ने किया एनपीसीएल का घेराव

एक मुश्त हो गांवों की बिजली का बिल : 24 घंटे मिले बिजली

कार्यालय प्रतिनिधि

ग्रेटर नोएडा। बिजली बिलों में नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल) की मनमानी के विरोध में ग्रेटर नोएडा के कई गांवों के किसान कल सड़क पर उतरे। उन्होंने पैदल मार्च निकाला और एनपीसीएल के नॉलेज पार्क एक स्थित कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कंपनी कार्यालय के गेट के बाहर करीब चार घंटे तक धरना दिया। ग्रामीणों की प्रमुख मांग है कि उनका बिजली बिल फिक्स किया जाए। उन्होंने एनपीसीएल पर ग्रामीण उपभोक्ताओं का शोषण करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। एहतियात के तौर पर कंपनी कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात रहा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एनपीसीएल मनमाने बिजली बिल भेज रही है। बिजली की खपत के सापेक्ष अधिक धनराशि के बिल भेजे जा रहे हैं। जबकि गांवों में बिजली आपूर्ति की स्थिति बेहद खराब है। प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 18 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश दे रखे हैं। हकीकत में ग्रामीणों को इसके अनुरूप बिजली नहीं मिल रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एनपीसीएल ग्रामीणों का आर्थिक रूप से शोषण कर मालामाल हो रही है। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की और गेट के बाहर धरने पर बैठ गए। करीब चार घंटे तक चले धरने को कई लोगों ने संबोधित किया और अपनी मांगों को रखा। कासना निवासी महिला कविता ने आरोप लगाया कि उसने 2017 में बिजली कनेक्शन विच्छेद (कटवा) करा दिया था। इसके बावजूद कंपनी ने उसे कानूनी नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलने के बाद वह कंपनी के अधिकारियों से मिलने गई, लेकिन उसे पिछले दो साल से कार्यालय के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एनपीसीएल व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में सांठगांठ है। उन्होंने एनपीसीएल के सीएजी ऑडिट की मांग की। लोगों की मांग है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल फिक्स किया जाए। गांवों में 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जाए। धरोहर राशि को समाप्त करने के अलावा उपभोक्ताओं को जारी नोटिस वापस लेने, जिन उपभोक्ताओं ने बढ़ी धनराशि के बिल का भुगतान किया है, उसे समायोजित करने से संबंधित मांगपत्र कंपनी के वीपी सारनाथ गांगुली को सौंपा। ग्रामीणों के लिए अलग काउंटर की मांग भी की गई। कंपनी ने ग्रामीणों की कुछ मांगों को मानते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि सभी मांग पूरी न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी

स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया

स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया श्री साईं धाम सेवा समिति स्थान व भटियारी चौधरी मोड़ बीकानेर वाले के पीछे गाजियाबाद में श्री साईं हनुमान मंदिर मैं स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया जिसमें बाबा का गुणगान प्रशांत सूर्यवंशी देवेंद्र चौधरी सविता चौधरी नवीन गुप्ता मोनू कैलाश सोनू सरगम साईं बाबा का गुणगान किया कार्यक्रम में उपस्थित महंत विजय गिरी जी महाराज महंत मनीष गिरी जी महंत संदीपन शर्मा जी महंत राजीव अग्रवाल जी अजय चोपड़ा चौधरी सुंदर भाटी आर के शर्मा आचार्य श्रीकांत पांडे जी उपस्थित थे

पुलिसकर्मियों से की मारपीट

नोएडा। लेबर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान चार युवकों ने खुद को पत्रकार बताकर पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। इसके बाद पुलिस और युवकों के बीच मारपीट हो गई। इस घटना के बाद कोतवाली सेक्टर–58 पुलिस ने चार फर्जी पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस वालों ने भी लेबर चौक पर कुछ निर्दोष युवकों के साथ बदसलूकी कर दी और थाने ले गए।

सेक्टर–58 के थानाध्यक्ष शावेज खान ने बताया कि एसआई प्रताप सिंह एक सिपाही के साथ लेबर चौक पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बाइक सवार को जांच के लिए रोका। बाइक पर नंबर प्लेट नहीं थी। उन्होंने बाइक को सीज कर दिया। इसके कुछ मिनटों के बाद बाइक सवार तीन अन्य युवकों के साथ वहां पहुंच गया। सभी लोग मिलकर पुलिसकर्मियों से बदसलूकी करने लगे। आरोप है कि चारों ने खुद को अलग–अलग संस्थान में पत्रकार बताकर दरोगा के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुला लिया गया। पुलिसकर्मियों ने चारों युवकों को पकड़ लिया। जांच की गई तो पता चला कि इनमें कोई पत्रकार नहीं है। आरोपियों की पहचान बुलंदशहर निवासी रविंद्र कनौजिया, जीतू, संदीप उर्फ गोलू और अविनाश के रूप में हुई। ये चारों फिलहाल खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं। पुलिस ने चारों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है।

नोएडा को प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने में करें सहयोग : माहेश्वरी

नोएडा। शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का अभियान शुरू किया गया। प्लास्टिक उठाने के लिए बड़े स्तर पर श्रम दान किया गया। पहले दिन 300 किलो प्लास्टिक एकत्रित की गई। इसे बैगों में भरकर सेक्टर–43 में एकत्रित किया गया। यह वही प्लास्टिक है जो शहर की सड़कों, पार्कों, ग्रीन बेल्ट व बाजारों से एकत्रित की गई। दो अक्टूबर तक 10 मेट्रिक टन प्लास्टिक एकत्रित की जाएगी। इस प्लास्टिक का ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

प्लास्टिक फ्री दीवाली करने के लिए केंद्र सरकार की योजना स्वच्छता ही सेवा की शुरूआत शहर में की गई। इसका उद्देश्य शहर को एकल प्लास्टिक प्रयोग से मुक्त करना है। सेक्टर–43 सोम बाजार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी ने हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरूआत की। जिसमें शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए आरडब्ल्यूए, ग्राम वासियों, प्राधिकरण अधिकारियों व कर्मचारियों ने श्रमदान किया। सीईओ माहेश्वारी ने आरडब्ल्यूए से अपील की वह अपने सेक्टर को प्लास्टिक मुक्त बनाने में प्राधिकरण का सहयोग करें। कहीं भी प्लास्टिक पड़ी दिखे तो उसे एकत्र कर चिन्हित स्थानों पर भेजें या डोर–टू–डोर कलेक्शन वाहनों को दें। ताकि प्लास्टिक से पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा न मिले इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जा सके। इस मौके पर सीईओ ने आए हुए लोगों को जूट के थैले बांटकर प्लास्टिक फ्री का संकल्प भी दिलाया। 11 सितंबर से 27 अक्टूबर तक शहर में प्लास्टिक वेस्ट श्रम दान अभियान चलाया जाएगा। इसकी शुरूआत की गई। यह अभियान तीन चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण 11 अक्टूबर से 01 अक्टूबर तक दूसरा चरण दो अक्टूबर को जिसमें शहर भर से श्रमदान के जरिए एकत्रित की प्लास्टिक का संग्रहण एक स्थान पर किया जाएगा। 3 से 27 अक्टूबर तक लोगों को प्लास्टिक सामग्रियों को रिसायकल करने के लिए जागरूक किया जाएगा। शहर से एकत्रित किया गया प्लास्टिक सीमेंट फैक्ट्रियों को भेजा जाएगा। जिसे कोयले के विकल्प के रूप में ईंधन की तरह प्रयोग में लाया जाएगा। इसके लिए सिमेंट फैक्ट्री एसोसिएशन से बातचीत हो चुकी है।

शहर में बनाए गए संग्रहण केंद्र

श्रमदान के जरिए एकत्रित किए गए प्लास्टिक का संग्रहण शहर के कई स्थानों पर किया जाएगा। इसमें सेक्टर–8 स्थित एजी इन्वायरो पार्किंग साईट, डी–5 सेक्टर–80 एजी एन्वायरो एफसीटीएस, सेक्टर–110 एजी एन्वायरो एफसीटीएस, एसपीएस सेक्टर–31,43,80,117 पर एकत्रित कर इसके निस्तारण के लिए सीमेंट फैक्टिरियों में भेजा जाएगा।

जगन्नाथ इंस्टीटडूट में बाल सुधारगृह का निरीक्षण किया

ग्रेटर नोएडा। विधिक जागरूकता अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत जगन्नाथ इंस्टीट्यूट आयोग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर, सचिव के आदेशो के अनुपालन में जगन्नाथ इंस्टीट्यूट , ग्रेटर नोयडा के विद्यार्थियों ने विधि विभागाध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता के नेतृत्व में विधिक जागरूकता के अंतर्गत फिरोज शाह कोटला स्थित बाल सुधार गृह का निरीक्षण किया।

विद्यार्थियों ने विचाराधीन बाल कैदियों से मुलाकात की और उनकी दिनचर्या के बारे में जाना।

सुधारग्रह के अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि किस तरह से इन बालको को मुख्य धारा में लाया जाता है और उन्हे हुनरमंद शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो आसानी से अपना भरण पोषण कर सके। इस मौके पर असिस्टेन्ट प्रोफेसर मानवेन्द्र सिंह, व नीरव खरे ने बताया कि इस तरह के [illegible] कार्यक्रम विद्यार्थियों को जागरूकता के साथ साथ रूचि भी बढ़ाते है और उनमें एक नवचेतना का विकास होगा।

जग्गनाथ इंस्टीट्यूट की विभागाध्यक्षा डॉक्टर पल्लवी गुप्ता ने विधिक जागरुकता को जन जन तक पहुचाने के लिए और जुवेनाइल संरक्षण के लिए जगन्नाथ इस्टीट्यूट की ओर से हर संभव मदद का आश्वाशन भी दिया। इस अवसर पर पैरा लीगल वॉलेंटियर श्री नरेंद्र शर्मा, विधि विद्यार्थी अरुणिम, निखिल, अनीस, प्रियंका, [illegible]न्या, अमीषा, आसिफ, गौतम, आलोक, इत्यादी भी मौजूद रहे।

ग्रेटर नोएडा से दादरी के लिए बस सेवा जल्द

ग्रेटर नोएडा। परी चौक से दादरी के लिए बस सेवा अगले सप्ताह संचालित होगी। परिवहन विभाग ने परी चौक से अल्फा, बीटा होते हुए नॉलेज पार्क फोर्थ मेट्रो स्टेशन से होकर वाया तिलपता गोल चक्कर से दादरी रोडवेज बस स्टेशन तक बस सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। आर्य प्रतिनिधि सभा के जिला उपाध्यक्ष डॉ. आनंद आर्य ने बताया कि इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी करा ली गई हैं। पहले भी परी चौक से सूरजपुर होकर दादरी के लिए बस सेवा संचालित हुई थी लेकिन यह रूट काफी लंबा पड़ता है। इसको लेकर नए रूट के लिए परिवहन विभाग से अनुरोध किया गया था, जिसे मान लिया गया है।

कांग्रेसियों ने निकाला लालटेन जुलुस

गाजियाबाद। भाजपा सरकार द्वारा बिजली की दरो मैं बेतहाशा वृद्धि तथा पेट्रोल डीजल के आसमान छुते दाम से जनता में त्राहि दृत्राहि मची हुई हैं आज पूरा देश मंदी की मार से जूझ रहा हैं नोजवानो को नोकरियां नहीं व्यापारियों के पास काम नहीं रियल स्टेट पूरी तरह से चोपट हैं किसान, मजदुर, नोजवान पूरी तरह त्रस्त हैं महगाई अपनी चरम सीमा पर है।

जनता की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेन्द्र भारद्धाज के नेतृत्व में लालटेन जुलुस निकाला गया जिसमे बिजेंद्र यादव ए. आई. सी. सी. सदस्य, विजय चौधरी ऐ.आई.सी.सी. सदस्य, जाकिर सेफी ऐ.आई.सी.सी. सदस्य, डा.संजीव शर्मा पी.सी.सी. सदस्य, अनीश खान पी.सी.सी सदस्य, शिराजुद्दीन सेफी, के.के.शर्मा पूर्व विधायक, वी.के. अग्निहोत्री पी.सी.सी. सदस्य, सत्यप्रकाश सत्तो पार्षद, विजय गोयल पार्षद, मांगे राम त्यागी सेवा दल अध्यक्ष, मनोज कोशिक यूथ अध्यक्ष, रोहित वाशिंगटन, सुनील चोधरी पूर्व पार्षद, शिवानन्द गोड, अनुज चौधरी, रवि चौधरी, जफीर आलम, जीतेन्द्र गोड, पी.एन. शर्मा, मनेन्द्र सिंह बिल्ला, इमरान खान, फिरोज इदरीसी, गौरव पंडित, एम. के. शर्मा, मो. आमिर, आदि तमाम कांग्रेसी उपस्तिथ रहे।

कुछ यादें हुई ताजा

सुशील शर्मा के साथ विधान चन्द्र गर्ग

आज अपने पुराने मित्र 1981 से 1995 तक दै. हिन्दुस्तान के संवाददाता रहे विधान चन्द्र गर्ग (सर्राफ) से बहुत दिन बाद मिलना हुआ। इस परिवार की तीन पीढी लगातार 7 दशक तक पत्रकारिता से जुडी रही हैं। विधान जी के पिता स्व. चन्द्र भान गर्ग (1907–1981) इस महानगर के पहले पत्रकार थे। जो 1936 में दै. हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स के अलावा उर्दू के मिलाप, प्रताप और तेज के भी पहले संवाददाता थे। स्वतंत्रता आन्दोलन में 1932 से 1942 तक वह कई बार जेल में बंद रहे। जेल में चक्की पीसना व खाट के बान बटने का काम उनसे लिया गया। उनके पैरों में बेडियाँ पडी होती थीं। वह सर्राफा एसो. के अध्यक्ष के अलावा श्रीकृष्ण गौशाला व वैश्य सभा के भी महामंत्री रहे। मुझे सौभाग्य प्राप्त है कि 1976 में गाजियाबाद जिला बनने से पूर्व से उनके निधन तक गाजियाबाद पत्रकार संघ के वह अध्यक्ष और मैं महामंत्री रहा। हम दोनों का उस समय विजिटिंग कार्ड भी एक होता था। मेरठ मंडल के वरिष्ठ पत्रकारों के अनेक सम्मेलनों में उनके साथ पत्रकारों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला। उनके निधन के बाद उनके पुत्र विधान चन्द्र गर्ग (81 वर्ष) 1981 से 1995 तक दै. हिन्दुस्तान के संवाददाता रहे। वह भी सर्राफा एसो. के अध्यक्ष रहे हैं। विधान चन्द्र गर्ग के प्रतिभावान एक मात्र पुत्र स्व. संदीप गर्ग (1966–2012) का निधन अल्पायु में हो गया था। वह एमएससी (आर्गेनिक कैमिस्ट्री) थे। वह भी सर्राफा एसो. के अध्यक्ष रहे। वह भी भारी मत से चुनाव जीत कर। परिवार की यह तीसरी पीढी भी पत्रकार रही। अपने अन्त समय वह दै. पंजाब केसरी के ब्यूरो चीफ थे।संदीप ने गाजियाबाद का पेज खुद बनाकर भेजने की शुरूआत की थी।संदीप के पुत्र कुशाग्र अपनी उच्च शिक्षा के साथ अपने बाबा के साथ सर्राफा व्यवसाय में मदद करते हैं। विधान चन्द्र गर्ग की लैब का बना सोने का पावडर मार्किट में प्रसिद्ध है।

उल्लेखनीय है चन्द्र भान गर्ग जी के पिता श्री दुर्गा प्रसाद 'सलिल' श्रीसुल्लामल रामलीला की रामायण के रचियता थे।ब ताया जाता है श्री सुल्लामल जी दृष्टीहीन थे अतरू उन्होंने बोलकर उनसे लिखवायी। उन्होंने सर्राफा पर 'आईना ए इल्मो हुनर सर्राफा' पुस्तक भी लिखी थी। इस परिवार की एक और शख्सियत चन्द्र भान गर्ग जी के छोटे भाई सूरज भान गर्ग (1925 से 1983) थे। वह अपने जमाने में दै. हिन्दस्तान टाइम्स सहित सात अंग्रेजी अखबारों के संवाददाता रहे। 1947 में विभाजन के समय दंगे भडकने के समय उनकी गढगंगा मेले की रिपोर्टिंग पर उस समय अखबार के सम्पादक देवदास गांधी(महात्मा गांधी के पुत्र) ने उन्हें 50रू. का पुरस्कार दिया था। सूरज भान गर्ग 'अग्रसेन धर्मशाला' के भी संस्थापकों में थे। स्व. आशा राम पंसारी को साथ लेकर उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। वह जीवन पर्यन्त श्री सुल्लामल रामलीला कमेटी के उस्ताद और महामंत्री रहे। उस समय वैश्य वर्ग के वह एक मात्र दबंग नेता थे। उस समय शहर में लोकल गुंडागर्दी चर्म पर थी पर किसी बदमाश की उनका सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी।

4 दिन बंद रहेंगे बैंक, निपटा लें काम

नोएडा। इस महीने लगातार चार दिन बैंक में कामकाज नहीं होगा। 26 व 27 सितंबर को दो दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल है, जिसमें सभी बैंकों के अधिकारी शामिल होंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों की चार यूनियनों ने दस सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा के विरोध में 26 सितंबर से दो दिन की हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इसके अलावा, 28 सितंबर को भी बैंक में काम नहीं होंगे, क्योंकि महीने के अंतिम शनिवार को बैंकों में छुट्टी रहती है और 29 सितंबर को बैंक में रविवार की छुट्टी रहेगी।

सरकार ने दस सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का विलय कर चार बैंक बनाने की घोषणा की है। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) को भेजे नोटिस में अधिकारियों की यूनियनों ने कहा कि उनका बैंकिंग क्षेत्र में विलय के खिलाफ हड़ताल पर जाने का प्रस्ताव है। सरकार ने 30 अगस्त को सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों का एकीकरण कर चार बैंक बनाने की घोषणा की थी। यूनियन के नेता ने यह भी कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। आल इंडिया बैंक आफिसर्स कनफेडरेशन (एआईबीओसी), आल इंडिया बैंक आफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए), इंडियन नेशनल बैंक आफिसर्स कांग्रेस (आईएनबीओसी) और नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स (एनओबीओ) ने संयुक्त रूप से हड़ताल का नोटिस दिया है। इसके अलावा बैंक यूनियनों की पांच दिन का सप्ताह करने और नकद लेनदेन के घंटों और विनियमित कार्य घंटों को कम करने की भी मांग है। यूनियनों ने सतर्कता से संबंधित मौजूदा प्रक्रियाओं में बाहरी एजेंसियों का हस्तक्षेप रोकने, सेवानिवृत्त कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों को सुलझाने, पर्याप्त भर्तियां करने, एनपीएस को समाप्त करने और उपभोक्ताओं के लिए सेवा शुल्क कम करने और अच्छा प्रदर्शन नहीं करने के नाम पर अधिकारियों को परेशान नहीं करने की मांग की है। एआईबीओसी (चंडीगढ़) के महासचिव दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि देशभर में राष्ट्रीयकृत बैंक 25 सितंबर मध्यरात्रि से 27 सितंबर मध्यरात्रि तक हड़ताल पर रहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के विरोध और अपनी अन्य मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा कि नवंबर के दूसरे सप्ताह से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार ने दस राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय कर चार बड़े बैंक बनाने की घोषणा की है। इसके तहत यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया और ओरियंटल बैंक आफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया जाएगा। इसके बाद अस्तित्व में आने वाला बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा बैंक होगा। इसी तरह सिंडिकेट का विलय केनरा बैंक में किया जाएगा। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में होना है जबकि आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक आफ इंडिया में मिलाया जाएगा।

कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसान मेले का शुभारंभ

दादरी। छौलस गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में तीन दिवसीय किसान मेले व कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। मेले का शुभारंभ गौतमबुद्ध नगर के सांसद डा. महेश शर्मा ने फीता काटकर किया। मेले में गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, अलीगढ़ समेत कई जिलों के किसान शामिल हुए। कार्यशाला के पहले दिन किसानों को जैविक खेती करने के तरीके बताए गए। कार्यशाला में बुलंदशहर, संत कबीर नगर, उत्तराखंड आदि स्थानों के करीब पांच सौ किसानों ने हिस्सा लिया।

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को जैविक खेती के लाभ, उन्नत खेती करने के लिए बीज व उपकरणों की जानकारी दी। इस मौके पर डा. महेश शर्मा ने किसानों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए जैविक खेती करने का आह्वान किया। कार्यशाला में जैविक खेती के लिए नई तकनीकी, मृदा जांच, गुणवत्ता युक्त बीज, उपकरण आदि की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र गौतमबुद्ध नगर, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद, कृषि विज्ञान केंद्र हापुड़, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के सहयोग से किया गया। इस मौके पर जगपाल सिंह, डा. मयकं, डा. हंसराज, डा. अरोवद कुमार, टीपी राजन, एनएन शुक्ला, दीप्ति चौधरी, डा. एन मिश्र व डा. कुंवर घनश्याम आदि ने कार्यशाला को संबोधित किया।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक व मुद्रक श्रीमति कुसुमलता भाटी ने वर्तमान ऑफसेट याकूबपुर गांव, हॉजरी कांप्लैक्स, फेज–2, नोएडा गौतमबुद्धनगर से छपवाकर याकूबपुर गांव, हॉजरी कांप्लैक्स, फेज–2, नोएडा गौतमबुद्धनगर से प्रकाशित किया। संपादक : शोभाराम भाटी, विधि सलाहकार एस. डोगर एडवोकेट, आर.एन.आई. नं. 72344/98, मो. नं. : 9810420278

E-maill: vartmansatta@ yahoo.com

चीन और कोरिया के उद्यमी

ग्रेटर नोएडा में कर रहे हैं सबसे अधिक निवेश

ग्रेटर नोएडा। चीन और कोरिया के उद्यमी ग्रेटर नोएडा में सबसे अधिक निवेश कर रहे हैं। दिल्ली–मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इंटिग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाई जा रही है। यह टाउनशिप दिल्ली–कानपुर रेलवे लाइन और ग्रेटर नोएडा के बीच अलग से 747 एकड़ में है। टाउनशिप में लगी इंडस्ट्री में काम करने वालों के लिए एक ही छत के तले सभी बुनियादी सुविधाएं होंगी। दो साल में हजारों लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस टाउनशिप में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और कलपुर्जों का निर्माण होगा।

ग्रेनो अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि इंटिग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप में विश्व स्तरीय सुविधाओं को देखते हुए चीन की कंपनी सबसे अधिक निवेश करने के लिए आकर्षित हो रही है। चार कंपनी अभी तक 3900 करोड़ रुपये का निवेश कर चुकी हैं। ये कंपनियां अगले साल तक अपना उत्पादन शुरू कर देंगी। इनके चालू होने से करीब दस हजार लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। इनके बन जाने से अपरोक्ष रूप से भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। इनमें चीन की हायर कंपनी सबसे अधिक तीन हजार करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इसी तरह कोरिया की कंपनियों की भी ग्रेटर नोएडा पसंद बनता जा रहा है। यहां पर पहले से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा अन्य कंपनियां हैं। इनके अलावा हाल में सेक्टर इकोटेक–10 में कोरियाई कंपनी को 35 एकड़ का प्लॉट दिया गया है। यह कंपनी 550 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। चार हजार लोगों को सीधे रोजगार देगी। इससे पहले कोरिया की 8 कंपनियों ने अपना कारोबार शुरू करने के लिए प्लॉट के लिए आवेदन किया है। इन कंपनियों के शुरू होने से 12 हजार लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा।

क्या है इंटिग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप :– ग्रेनो के दादरी से लेकर मुंबई तक 1483 किमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा इसका मुख्य केंद्र है। इसके तहत ग्रेटर नोएडा में पहले चरण में 747 एकड़ एरिया में इंटिग्रेटिड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बसाई जा रही है। यहां से उद्यमी अपना कच्चा और पक्का माल सीधे ट्रेन के जरिए मुंबई के नेहरू पोर्ट बंदरगाह भेज सकते हैं। यहां से माल को विदेश भेजने और मंगाने की सुविधा होगी।

अब गाजियाबाद में बिजली चोरों की खैर नहीं, खुलेगा बिजली थाना

गाजियाबाद। बिजली चोरी रोकने के लिए पॉवर कॉरपोरेशन ने हर जिले में एंटी पॉवर थेप्ट थाना खोलने की कवायद काफी पहले ही शुरू कर थी। अगर सबकुछ ठीक ठाक रहा तो सितंबर के अंत तक जिले में भी ऐसा ही एक थाना खुल जाएगा। यह थाना पांचों सर्किल में बिजली चोरी रोकने का काम करेगा। मुख्य अभियंता आरके राणा का कहना है कि थाना खुलने से विभाग के कर्मचारियों की कार्यक्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। वर्तमान में गाजियाबाद जोन के पांचों जोन में बिजली की मांग 1400 मेगावाट से 1500 मेगावाट के बीच है। इसमें करीब 20 से 22 फीसदी लाइन लॉस है। इसमें 10 प्रतिशत तकनीकी लाइन लॉस हटा दें तो 10 से 12 फीसदी बिजली चोरी हो जाती है। यानि लगभग 280 से 300 मेगावाट बिजली आपूर्ति ऐसी होती है जिसका पैसा विभाग को नहीं मिलता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह बिजली किसी न किसी रूप में चोरी होती है। विभाग को इससे सीधे राजस्व का नुकसान होता है। विभाग ने इस चोरी को रोकने के लिए एक कदम और बढ़ा दिया है। सितंबर के अंत तक वसुंधरा सेक्टर आठ में थाना खुल जाएगा। विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल एंटी थेप्ट थाने के लिए वसुंधरा सेक्टर–8 स्थित विद्युत सब स्टेशन में जमीन फाइनल की गई है। बिजली चोरी के मामलों की विवेचनाओं का जल्द जल्द निस्तारण हो सके, इसलिए यह थाना खोला जाएगा। मुख्य अभियंता आरके राणा ने बताया कि एंटी पॉवर थेप्ट थाने की काफी समय से प्लानिंग चल रही है,मगर अड़चनों के चलते खोला नहीं जा सका। स्टाफ मुहैया हो जाने और थाने के लिए जमीन मिल जाने के बाद अब इसकी शुरूआत सितंबर अंत तक हो जाएगी। स्टॉफ की भी नियुक्ति कर दी गई। वसुंधरा सेक्टर–8 में खोले जाने वाले थाने में स्टॉफ की नियुक्ति कर दी गई है। थाने में तैनात स्टाफ बिजली चोरी के मामलों का ही निस्तारण करेगा। थाने में बिजली चोरी से सम्बंधित मामलों को दर्ज कर उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। एंटी पॉवर थेप्ट थाने में बिजली चोरी के मामलों का ही निस्तारण किया जाएगा। एंटी पॉवर थेप्ट थाने में एक प्रभारी निरीक्षक, 3 दारोगा और 10 सिपाही की नियुक्ति की गई है। थाना शुरू होने के बाद पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई जा सकेगी। अभी तक बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जाने वाले अभियान के दौरान विजिलेंस और सिविल पुलिस के सहयोग से कार्रवाई की जाती है। लेकिन अब बिजली थाना का स्टाफ खुद कार्रवाई करेगा।

बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर नॉलेज पार्क में सेमिनार का आयोजन किया

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित लॉयड लॉ कॉलेज में महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश एवं लीगल ऐड सेल लॉयड लॉ कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश की अध्यक्ष विमला बाथम थीं।

इस अवसर पर उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के विकास में कानून का निर्माण किया गया है। इसके गर्भ में पल रहे बच्चे का लिग परीक्षण करना निषेध है। इस कानून से देश में घटते लिगानुपात को बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। बेटी की समाज में अहम भूमिका होती है। आज समाज के विभिन्न वर्गों में बेटियां नेतृत्व कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बेटियों को लाभावित करने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजना ला रही है। कॉलेज के अध्यक्ष मनोहर थरानी ने कहा लॉयड कॉलेज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कथन के विकास के लिए काम करता है। छात्राओं को पढाई में पच्चीस हजार रुपए की छात्रवृत्ति भी देता है। इस अवसर पर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अनुराग भार्गव, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी सहित अन्य लोगों ने भी अपने विचार रखे।

महिलाएं व्हाट्स एप नम्बर पर करें अपनी शिकायत : सुषमा सिंह

पीड़िता की न सुनने पर पुलिस अधिकारियों को फटकारा

मेरठ। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने जनपद का दौरा कर सर्किट हाउस में जनसुनवाई कर समस्याओं का निस्तारण किया तथा अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको महिलाओं व पीड़िताओं से अच्छा व्यवहार रखने तथा उनकी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए कहा। उन्होंने जनसुनावाई के दौरान पीड़िता की न सुनने पर पुलिस अधिकारियों की फटकार लगाई तथा कहा कि पीड़ित महिलाएं अपनी शिकायत आयोग के व्हाट्स एप नम्बर 6306511708 पर दे सकतीं हैं।

सर्किट हाउस में जनसुनवाई के दौरान आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने तीन प्रकरणों की सुनवाई कर दो का मौके पर ही निस्तारण कर दिया तथा एक के निस्तारण के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की काउंसिलिंग की जाए तो मामले का निस्तारण आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों की भी काउंसिलिंग जहां आवष्यकता होगी वहां कराने पर विचार किया जाएगा ताकि वह अपना व्यवहार पीड़िता व महिलाओं के प्रति अच्छा रखें। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए उपाध्यक्ष सुषमा सिंह ने कहा कि पुलिस व अन्य प्रशासनिक अधिकारी महिलाओं का दर्द समझें व उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए उन्हें आश्वस्त व संतुस्ट करें। उन्होंने कहा कि जनता जागरुक है इसलिए उसकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें। उन्होंने प्रोविजन अधिकारी को निर्देशित किया कि वह मेडिकल कालेज मे स्थापित 181 सेंटर में महिला कांस्टेबलों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बायोमेट्रिक मशीन लगाएं। जिला प्रोवेजन अधिकारी शत्रुधन कन्नौजिया ने बताया कि गत अगस्त माह में 181 सेंटर में 84 कॉल प्राप्त हुईं सभी का निस्तारण कर दिया गया है।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ राजकुमार, प्रभारी उपनिदेषक प्रोविजन महेष कंडवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी मोहम्मद मुस्ताक, महिला थाने की इंस्पेक्टर सहित अन्य पुलिस व प्रषासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

साहित्य के बिना फिल्में अधूरी

नोएडा। नृत्य की भी अपनी कला होती है जिसमे आप अपने आपको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते है आज नृत्य के जरिए समाज की कुरीतियों को भी बखूबी दिखाया जा सकता है और अच्छाइयों को भी, पहले के नृत्य हमारी जातक कथाओ या कृष्ण लीलाओं पर ही ज्यादा फोकस किया जाता था लेकिन आप शिक्षा, बेरोजगारी या महिलाओ के साथ होने वाले दुराचार को नृत्य के जरिए पेश किया जा रहा है यह कहता था प्रसिद्ध नृत्यांगना शोवना नारायण का जिन्होंने पांचवे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के दूसरे दिन शिरकत की। इस अवसर पर मंगोलिया के राजदूत एच.ई. गोंचिग गम्बोल्ड, योग आचार्या अनीता दुआ, एंकर यासिर उस्मान उपस्थित हुए।

इस अवसर पर संदीप मारवाह ने छात्रों को सम्बोधित करते हुए कहा की बिना साहित्य के हम फिल्मों की कल्पना भी नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी फिल्म को बनाने से पहले उसकी स्टोरी, उसका स्क्रीनप्ले, स्क्रिप्ट साहित्य में ही आता है क्योकि इनके चुने हुए शब्दों को जोड़कर ही एक अच्छी फिल्म का निर्माण होता है। गोंचिग गम्बोल्ड ने कहा कि भारतीय साहित्य से मैं स्वयं को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ क्योंकि मेरे माता पिता के नाम का अर्थ मंगोलियन भाषा में नहीं मिला तो मैंने इंडिया आकर उनके नाम का अर्थ खोजा तो मुझे पता चला की मेरे माता पिता का नाम संस्कृत भाषा के किसी शब्द का अर्थ है और मुझे यह जानकर काफी खुशी हुई इसीलिए में अपने आपको भारत से जुड़ा महसूस करता हूँ।

यासिर उस्मान ने कहा कि किसी भी साहित्य को भाषा में बांधा नहीं जा सकता और जो अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहकर लोगो को आकर्षित कर सकता है वो अच्छा लेखक बन सकता है। इस अवसर पर योग आचार्या अनीता दुआ और शोवना नारायण की पुस्तक ष्इलुमिनेटिंग इंडियन क्लासिकल डांसर थ्रू योगाष का भी विमोचन किया गया।

मेरठ एक्सप्रेस वे के निर्माण में

5 गांवों की भूमि ने पेच फंसाया

नगर संवाददाता

गाजियाबाद। दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे निर्माण में डासना से मेरठ खंड के बीच पांच गांव की जमीन का पेच फंसा हुआ है। मोदीनगर तहसील के एक गांव में किसानों ने अधिग्रहित भूमि का कब्जा एनएचएआई को नहीं करने दिया। जबकि डासना क्षेत्र के चार गांवों की जमीन पर काम ही शुरू नहीं हो पाया है। एनएचएआई ने जिलाधिकारी से मोदीनगर क्षेत्र के गांव की जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस बल देने की मांग की है। आज जमीन पर कब्जे के लिए अभियान चलाया जाएगा।

दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेस वे के चार चरणों में निजामुद्दीन–यूपी गेट तथा डासना–हापुड़ खंड ही पूरे हो पाए हैं। यूपी गेट–डासना खंड पर निर्माण तेजी से चल रहा है। सबसे बड़ा पेच डासना–मेरठ खंड पर है। मोदीनगर क्षेत्र के गांव जैनुद्दीनपुर की 6.89 हेक्टेयर भूमि का इसी वर्ष जून में अधिग्रहण पूरा किया गया। जुलाई में अवार्ड भी घोषित कर दिया गया। एनएचएआई ने एडीएम (भूअ) को प्रतिकर भुगतान के लिए उपलब्ध करा दी, लेकिन एनएचएआई मौके पर काम नहीं करा पा रहा है। क्योंकि किसान अधिग्रहित जमीन पर कब्जा नहीं करने दे रहे हैं। इस वजह से एक्सप्रेस वे का निर्माण अटका हुआ है। एनएचएआई ने जिलाधिकारी से पुलिस बल के सहारे कब्जा दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही डासना क्षेत्र में चार गांव की 19 हेक्टेयर जमीन पर भी काम शुरू नहीं हो सका है। डासना, रसूलपुर सिकरोड़, नाहल और कुशलिया की जमीन का प्रतिकर रूका हुआ है। इसकी वजह से 3.25 किलोमीटर सड़क का निर्माण शुरू ही नहीं हो पाया है।

बिजली के 13 खंभे एक सप्ताह में होंगे शिफ्ट

विजयनगर से लाल कुआं की तरफ हाइटेंशन लाइन के 13 खंभे हटाने की तैयारी शुरु हो गई है। पूर्व में इन खंभों को हटाने की समयसीमा 31 अगस्त थी, लेकिन शटडाउन ना मिलने की वजह से काम में देरी हुई है। तीन खंभे हटाए जाने बाकी हैं।

काला पत्थर की दूसरी लेन चालू होने में समय लगेगा

इंदिरापुरम में एक्सप्रेस वे से सटे काला पत्थर कट की दूसरी लेन चालू करने में समय लगेगा। खुदाई में बिजली की केबल जमीन से डेढ़ फुट नीचे मिलने की वजह से परेशानी हो रही है। यह परेशानी एक्सप्रेस वे से इंदिरापुरम जाने वाली लेन पर है।

दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा करने की तैयारी

एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर आरपी सिंह ने बताया कि डीएमई की समय सीमा मई 2020 है लेकिन प्रयास इस बात का किया जा रहा है कि इस वर्ष दिसंबर तक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। पहले चरण का काफी पहले ही लोकार्पण हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का करीब 60 फीसदी काम पूरा हो चुका है। इसमें लालकुआं पर आरओबी के चलते थोड़ा समय लग रहा है।

अब ट्रेनों में टिकटों के लिए नहीं होगी मारामारी

नई दिल्ली। भारतीय रेल इस फेस्टिव सीजन रिजर्वेशन कराने वालों के लिए खुशी की खबर लेकर आई है। दुर्गा पूजा, दीवाली, छठ जैसे त्योहारों के लिए पहले से ही एडवांस में टिकट बुक हो चुके हैं। खास तौर पर यूपी, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में निर्धारित सीटों से ज्यादा टिकट बिक चुकें हैं। हाल ही में रेलवे ने घोषणा की कि डेली बेसिस पर 4 लाख अतिरिक्त सीटें कई ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए भारतीय रेल ने ट्रेनों में सीटों को बढ़ाने के लिए नई HOG तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इस तकनीक की वजह से लंबी दूरी की ट्रेनों में अतिरिक्त सीटें उपलब्ध हो जाएंगी और यात्रियों को टिकट के लिए मारा–मारी नहीं करनी पड़ेगी।

क्या है HOG तकनीक? HOG मतलब है 'हेड ऑन जेनरेशन' तकनीक। यह तकनीक ट्रेन के पावर कार यानी की इंजन के बगल में अटैच होने वाले पावर या जेनरेटर कार में 25ॅ के ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर से ली गई इलेट्रिसिटी का इस्तेमाल ट्रेन के अंदर पावर स्पलाई के लिए करता है। आमूमन लंबी दूरी की ट्रेन में कुल 23 कोच होते हैं जिसमें एक पावर कार (EOG) आगे की तरफ और एक पावर कार पीछे की तरफ लगती है। इसके अलावा ट्रेन में 9 स्लीपर कोच, एक पैंट्री कार और 7 एसी कोच लगे होते हैं। हेड ऑन जेनरेशन तकनीक ट्रेन के इंजन से पावर लेकर EOG में बने इलेक्ट्रिक हब को बिजली पहुंचाता है, जिसे ट्रेन के कोचों में पहुंचाया जाता है। इस समय भारतीय रेलवे राजधानी, शताब्दी समेत कई ट्रेनों में इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है।

कैसे बढ़ेंगी अतिरिक्त सीटें? HOG तकनीक का इस्तेमाल लंबी दूरी की ट्रेनों में लगने वाले अतिरिक्त पावर या जेनरेटर कार EOG (एंड ऑन जेनरेशन) की जगह पर एक स्लीपर कार को अटैच किया जाएगा। एक LHB (लिंक हॉफमैन बुश) स्लीपर कोच में 78 सीटें होती हैं, ऐसे में लंबी दूरी की एक ट्रेन में रोजाना 78 सीटें बढ़ जाएगी। लंबी दूरी की ट्रेनों में लगने वाले दो EOG की जगह पर केवल एक ही EOG या पावर कार का इस्तेमाल किया जाएगा। यह पावर कार ट्रेन में इमरजेंसी की स्तिथि में बिजली पहुंचाने का काम करता है। HOG तकनीक के इस्तेमाल से न सिर्फ भारतीय रेलवे को जेनरेटर के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की बचत होगी। साथ ही साथ पर्यावरण को भी इन जेनरेटर कार से निकलने वाले धुएं से निजात मिलेगी और प्रदूषण पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।

38 की उम्र में 20वीं बार हुई गर्भवती

बीड। मजलगांव की 38 वर्षीय लंकाबाई खराट 20वीं बार गर्भवती हैं। यूं तो उनकी पिछली कोई डिलिवरी अस्पताल में नहीं हुई है लेकिन इस बार उनकी जान पर खतरा है जिसे देखते हुए प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता अतिरिक्त सावधानी बरत रहे हैं। दरअसल, लंकाबाई का वजन सिर्फ 45 किलो है और डॉक्टरों को उनकी डिलिवरी को लेकर कई आशंकाएं हैं। लंकाबाई को किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके, इसके लिए उन्हें अस्पताल में डिलिवरी कराने के लिए मनाया गया है।

19 में से बचे सिर्फ 11 :– लंकाबाई के 16 सफल प्रसव रहे हैं, जबकि तीन गर्भपात हो गए। फिलहाल उनके 11 बच्चे हैं। बाकी पांच बच्चे प्रसव के कुछ घंटे या कुछ दिनों के अंदर मर गए।पिछले साल कूड़ा बीनने वाली लंकाबाई की डिलिवरी उनके पति ने कराई थी। हालांकि, बच्चा कुपोषित था और 5 महीने से ज्यादा नहीं जी सका। मजलगांव के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अनिल परदेसी ने बताया है कि इस बार लंकाबाई की जान को खतरा है। उन्होंने बताया कि लंकाबाई को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने की कोशिशें की गईं ताकि उनका समय–समय पर चेक अप हो सके, दवाएं मिल सकें और सभी टेस्ट किए जा सकें ताकि डिलिवरी आराम से हो।

डिलिवरी के बाद खतरा :– दरअसल, 38 साल की उम्र में ही 20 बार गर्भवती होने के कारण लंकाबाई के स्वास्थय पर असर पड़ा है। उनका वजन सिर्फ 45 किलो है जिससे उनके ऊपर पोस्ट–पार्टम हैमरेज का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि भारत में करीब 25.7 मैटरनल डेथ, पोस्ट पार्टम हैमरेज के कारण ही होती हैं। लंकाबाई अभी तक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपने चेकअप भी नहीं करा रही थीं। इसलिए ब्लॉक प्रशासन ने एक सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभामा सौंदरमल की मदद ली।

परिवार की चिंता :– बीड के अस्पताल में चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि वह स्ट्रेस में हैं। उन्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है। कूड़ा बीनकर मिलने वाले 100–300 रुपये में उनका घर चलता है। इसलिए वह अस्पताल में भर्ती होने नहीं जा रही थीं, क्योंकि उन्हें डर है, वह चली गईं तो बच्चे खाएंगे क्या। उनका कोई बच्चा पढ़ा–लिखा नहीं है। यहां तक कि उनका सबसे बड़ा बेटा 21 साल की उम्र में ही 3 बच्चों का पिता है। उनके हालात को देखते हुए प्रशासन ने 5 किलो अनाज, तेल और नमक के लिए राशन कार्ड जारी कर दिया है।

कॉन्स्टेबल ने दुलहन ढूंढने के लिए छोड़ दी नौकरी

हैदराबाद। एक पुलिस कॉन्स्टेबल की नौकरी कितनी मुश्किल होती है, यह किसी से छिपा नहीं है। हैदराबाद के चारमीनार पुलिस स्टेशन में एक 29 साल के पुलिस कॉन्स्टेबल ने कुछ दिनों पहले नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया। अपने लेटर में कॉन्स्टेबल ने लिखा कि वह अपनी नौकरी को लेकर काफी व्यथित और अवसाद में है। लड़की वालों ने यह कहते हुए रिश्ते से इनकार कर दिया कि कॉन्स्टेबल की नौकरी काफी लंबी होती है और प्रमोशन के अवसर भी काफी कम होते हैं। कॉन्स्टेबल का नाम सिद्दांती प्रताप है जिन्होंने 2014 में कॉन्स्टेबल के रूप में पुलिस विभाग जॉइन किया था। वह हमेशा से पुलिस विभाग में शामिल होना चाहते थे लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को अपना इस्तीफा भेज दिया। अपने पत्र में उन्होंने लिखा, श्मैंने इंजिनियरिंग में अपना ग्रैजुएशन पूरा किया था और पुलिस विभाग में शामिल होने की प्रबल इच्छा से मैंने नौकरी जॉइन की।

अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, श्कुछ दिनों पहले एक लड़की वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। बाद में पता चला कि शादी का प्रपोजल नौकरी के लंबे घंटे के चलते मना किया गया था। लड़की के घरवालों का कहना था कि एक कॉन्स्टेबल की नौकरी काफी लंबी होती है जो कि कभी–कभार 24 घंटे भी खिंच जाती है। उन्होंने अपने लेटर में यह भी लिखा कि कैसे उनकी नौकरी में ग्रोथ का चांस न होना भी इस्तीफा देने की एक वजह है। उन्होंने कहा कि सब–इंस्पेक्टर और एक हाई रैंक के अधिकारी को नौकरी में प्रमोशन और फायदा मिल जाता है लेकिन कॉन्स्टेबल सालों तक उसी पद पर बना रहता है। सिद्दांती ने लेटर में लिखा, मैंने अपने सीनियर कॉन्स्टेबलों को देखा है जो 30– 40 साल तक नौकरी में बिना प्रमोशन के इस्तीफा दे चुके हैं। एसआई और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों को नौकरी में प्रमोशन और फायदे मिलते हैं लेकिन कॉन्स्टेबल के लिए प्रमोशन और दूसरे भत्ते की कोई सुविधा नहीं है।

पापा पीटेंगे, अंकल प्लीज बता दीजिए चालान तो नहीं हुआ...

लखनऊ। किशोर : अंकल मेरी स्कूटी का नंबर यूपी 32 एक्सवाई है, इसका चालान भरना है..., आपरेटर रू ई–चालन का प्रिंटआउट या मोबाइल पर आए मैसेज को दिखाओ। किशोर रू अंकल वो तो नहीं है। आपरेटर रू फिर नहीं जमा होगा। किशोर रू पापा बुहत पीटेंगे, अंकल प्लीज देखकर बता दीजिए, हुआ कि नहीं... इस तरह के संवाद आजकल रोजाना टीपी लाइन में ई–चालान जमा करते वक्त सुनने को मिल रहे हैं। यहां पर चालान जमा करने वालों के साथ ही अपने चालान की जानकारी जुटाने वालों की भी संख्या बहुत है। यातायात विभाग इसे सकारात्मक रूप से देख रहा है कि नियमों की सख्ती और चालान राशि के बढने से नाबालिग वाहन चालक यातायात नियमों के प्रति संवेदनशील हो रहे हैं। वह पापा की डांट और कानूनी कार्रवाई के डर से वाहन चलाने में कतराने लगे हैं। यही वजह है कि चोरी छुपे पिछले दिनों बाइक चलाने के चलते कहीं चालान तो नहीं कट गया, इसके लिए टीपी लाइन जाकर इसकी पड़ताल कर रहे हैं।

नाबालिग के वाहन चलाने के भी हो रहे चालान

नाबालिगों के वाहन चलाने पर चालान तो हो रहे हैं, लेकिन पुरानी वाली ही दर से। वहीं अभिभावक नाबालिग बेटे के चलान होने पर बिना कोई बहस किए चालान भरकर निकल जा रहे हैं। उन्हें डर है कि यदि चालान का शमन शुल्क नहीं भरा तो कोर्ट में नए नियम के तहत कार्रवाई न हो जाए। साथ ही बच्चों को दोबारा ऐसा करने पर बालिग होने पर भी वाहन न देने तक की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसे ही राजेंद्रनगर निवासी एक पिता ने बेटे के बिना बताए बाइक लेकर नरही निवासी दोस्त के घर चले आने पर हुए तीन हजार के चालान को चुपचाप भर दिया। उन्होंने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि ई–चालान से बेटे के नाबालिग होने का आकलन कैसे किया पता नहीं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के चक्कर में न पडना पड़े, इसलिए शमन शुल्क भर दिया।

34 संगठन 17 सितंबर को संसद का घेराव करेंगे

नोएडा। एक सितंबर से दिल्ली के साथ इससे सटे राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 लागू होने के बाद भारी–भरकम चालान ने लोगों के साथ इन राज्यों की सरकारों को भी परेशान करके रख दिया है। स्थिति यह है कि चालान कम करने को लेकर सिर्फ दिल्ली–एनसीआर के ही 34 संगठन 17 सितंबर को संसद का घेराव करेंगे। अगर मांगें नहीं मानी गईं तो 19 सितंबर को चक्का जाम करने की भी तैयारी है। इस बीच जैसा की उम्मीद की जा रही है कि अगर दिल्ली और यूपी में चालान कम हुए तो यह एक बड़ी राहत होगी। वैसे हरियाणा में अगले दो महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन वहां की सरकार इस तरह का कोई इशारा नहीं किया है। वहीं, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने चालान में कमी का इशारा किया तो अब गुजरात और उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में भी नए मोटर व्हिकल एक्ट, 2019 के तहत निर्धारित जुर्माने की राशि को कम करने पर विचार हो रहा है। ऐसा हुआ तो जल्द ही दिल्ली और यूपी के दो जिले गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद के करोड़ों लोगों को राहत मिलेगा। दिल्ली में ही 50 लाख लोगों को राहत मिलने की बात है। वहीं, बताया जा रहा है कि योगी सरकार जुर्माने में संशोधन की तैयारी में है, क्योंकि भाजपा शासित राज्य गुजरात में पहले ही चालान में 90 फीसद तक राहत प्रदान की जा चुकी है। यह भी गौर करने की बात है कि जून, 2019 में ही यूपी की भजापा सरकार मोटर यान नियमवाली 1988 की धारा 200 को संशोधित कर चुकी है। इन नियमों के तहत बगैर हेलमेट, बिना नंबर प्लेट के साथ बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर चालान में इजाफा किया गया था।

अपनी सरकार के लिए खतरा बन गए दिग्विजय?

सिंधिया विवाद से एमपी में बढ़ी गुटबाजी

नई दिल्ली। लंबे अरसे बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में लौटी कांग्रेस के लिए कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। एक तरफ पार्टी जहां आपसी गुटबाजी और उठापटक से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व सीएम और दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह लगातार पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। दरअसल, पिछले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो भी आपसी आरोप–प्रत्यारोप सामने आए हैं, वह वहां के दिग्गजों की आपसी गुटबाजी का नतीजा हैं। यह सारी गुटबाजी सरकार और पार्टी में पकड़ को लेकर है।

दिग्गी–ज्योतिरादित्य में सालों पुरानी है खींचतान

दरअसल, असली संघर्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच माना जा रहा है। ये खींचतान नई न होकर सालों पुरानी है। प्रदेश में एक धड़ा सिंधिया का है तो दिग्विजय और सीएम कमलनाथ एक गुट के माने जाते हैं। हाल के दिनों में दोनों गुट अपने–अपने समर्थकों के जरिए ताकत की आजमाइश में लगे हैं।

उल्लेखनीय है कि असली मामला प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर भी है। जहां सिंधिया की नजरें अध्यक्ष पद पर हैं, वहीं दिग्विजय नहीं चाहते कि सिंधिया के हाथों में कमान हो। दिग्विजय के खिलाफ हाल में सरकार में दखलंदाजी का आरोप लगाने वाले वन मंत्री उमंग सिंघार सिंधिया समर्थक समझे जाते हैं।

खुले तौर पर सामने आए मतभेद

गौरतलब है कि राज्य में सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच भी विवाद सतह पर आ चुके हैं। सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री एके एंटनी को सौंपा है। एंटनी की अध्यक्षता वाला पैनल जल्द ही सोनिया गांधी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। ऐसे में गत मंगलवार को ज्योतिरादित्य की कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ होने वाली बैठक टलने को लेकर एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि सोनिया गांधी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। इसलिए उन्होंने अपनी ये बैठक रद्द की है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में पार्टी के भीतर जारी इस उठापटक से कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बेहद नाराज है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रदेश के नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी न करने की हिदायत दी। सभी नेताओं के लिए गाइडलाइन जारी कर कहा कि कोई भी नेता बिना किसी ठोस सबूत के अपने किसी सहयोगी या साथी नेता पर आरोप नहीं लगाएगा।

दिग्विजय ने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक, सिंघार के हमले के बाद सिंह ने तय कर लिया है कि वे सिंधिया के हाथ में प्रदेश की कमान नहीं जाने देंगे। चर्चा तो यहां तक है कि अगर सिंधिया के हाथों में कमान जाती समिति के सामने है। है तो पार्टी में टूट–फूट हो सकती है। हालांकि, दिग्विजय का वरदहस्त और मार्गदर्शन लेकर मध्य प्रदेश के सीएम बनने वाले कमलनाथ भी सिंह की दखलंदाजी से असहज हैं, लेकिन सिंधिया के मुद्दे को लेकर वह भी सिंह के साथ हैं। कहा, यह भी जाता है कि मध्य प्रदेश के प्रशासन और अधिकारियों पर आज भी दिग्विजय सिंह की पकड़ काफी मजबूत है। यह बात कमलनाथ से लेकर कांग्रेस आलाकमान तक जानता है, इसलिए इस बात की संभावना कम ही है कि सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। दिग्विजय सिंह और सिंघार विवाद के बाद यह पूरा मामला फिलहाल कांग्रेस अनुशासन

जम्मू–कश्मीर के मुद्दे पर

बौरा रहा है पाकिस्तान, अब वजूद ही आ गया है खतरे में

नई दिल्ली। जम्मू–कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान जिस तरह बौरा रहा है उससे यही लगता है कि मजहब के नाम पर तामीर किये गये इस मुल्क का वजूद ही खतरे में आ गया है। भारतीय संघ के अभिन्न हिस्से इस राज्य में जिस तरह मानवाधिकारों के नाम पर संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशी ने इस राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में किये गये बदलाव के नाम पर घडिघ्याली आंसू बहाने का काम किया उससे यह तो सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान का जम्मू–कश्मीर पर किसी भी नुक्ते से कोई हक नहीं बनता है और वह स्वीकार करता है कि जम्मू–कश्मीर के लोग भारतीय संविधान के साये में जीते हैं।

कुरैशी के मुंह से परिषद की बैठक में यह निकलना कि भारत के राज्य जम्मू–कश्मीर में वर्तमान परिस्थितियों को लेकर वह चिन्तित हैं, बताता है कि पाकिस्तान 1947 से लेकर कश्मीर के मुद्दे को अपने वजूद को बनाये रखने की गरज से ही उठाता रहा है क्योंकि इस मुल्क की नापाक फौज ने दहशतगर्दी की तंजीमें खड़ी करके कश्मीर को लगातार मजहबी तास्सुब से 'पूर' करने की कोशिशें की हैं। अपनी इन कोशिशों में पाकिस्तान कभी सफल नहीं हो सका और अपने कब्जे में दबाये कश्मीर के हिस्से के लोगों पर जुल्म–ओ–गारत ढहाता रहा और इस इलाके में आतंकवादी शिविरों की फैक्टरी लगाकर उसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का अमन–चौन बर्बाद करने की ढान ली। अतः यह बेवजह नहीं है कि प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार के गृह मन्त्री श्री अमित शाह ने उस धारा 370 का पत्ता ही साफ कर दिया जिसका सहारा लेकर पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमें कश्मीरियों में अलगाववाद की भावना भरने के लिए वे तदबीरें भिड़ाती थीं जिनसे भारत की प्रभुसत्ता को निशाना बनाया जा सके। सवाल यह नहीं है कि भाजपा की 1951 से अपने जन्मकाल से ही धारा 370 समाप्त करने की घोषित नीति रही है बल्कि असली सवाल यह है कि समस्त भारतवासियों की स्वतन्त्रता के बाद से ही जम्मू–कश्मीर को भारत माता का ताज मानने की नीयत रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के सामान्य नागरिक ने हमेशा कश्मीर के लिए कुर्बानी देने से कभी गुरेज नहीं किया और हर मौके पर पाकिस्तान को साफ किया कि वे कश्मीरियों के हैं और कश्मीरी उनके हैं। अतः मानवाधिकार परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहीं विदेश सचिव (पूर्व) श्रीमती विजय सिंह ठाकुर का यह जवाब कि पाकिस्तान का काम कश्मीर के बारे में सिर्फ झूठ का प्रचार करना है और भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का है। दुनिया की कोई भी ताकत इस राज्य से धारा 370 समाप्त किये जाने के फैसले को चुनौती नहीं दे सकती क्योंकि यह फैसला भारत की स्वयंभू संसद ने किया है। आश्चर्यजनक यह है कि कुछ विपक्षी दलों के नेता इस मामले में पाकिस्तान का काम आसान कर रहे हैं और बिना सोचे–समझे बयानबाजी करके भारत के पक्ष को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही भारत में मानवाधिकारों की पैरोकार बनी गैर सरकारी संगठनों की ऐसी ब्रिगेड है जो जम्मू–कश्मीर के सम्पूर्ण विलय को मानवता विरोधी तक बताने से नहीं हिचकती और इस राज्य में सामान्य हालात बनते नहीं देख सकती।

दरअसल पाकिस्तान के लिए ही कश्मीर एक उद्योग नहीं है बल्कि ऐसी ब्रिगेड के लिए भी यह उद्योग बना हुआ है। खुद को मानवाधिकारों की अलम्बरदार बताने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जिस तरह करोड़ों रुपया बहाकर कश्मीर की हालत को खराब दिखाने की कोशिश की है उसी की वजह से पाकिस्तान ने भारत में सक्रिय इस ब्रिगेड के लोगों के कथनों का हवाला दिया है। सबसे दुखद यह है कि पाकिस्तान ने परिषद में रखे गये अपने दस्तावेजों में उमर अब्दुल्ला से लेकर शैला रशीद और कविता कृष्णन के वक्तव्यों को शामिल किया गया है। लोकतन्त्र हमें भारतीय संविधान के भीतर मानवीय अधिकारों की गारंटी देता है और राष्ट्र के प्रति अपने कर्त्तव्यों का भी बोध कराता है। धारा 370 समाप्त होने से जम्मू–कश्मीर की जनता के हकों में इजाफा हुआ है अथवा उनमें कमी आयी है? इस ब्रिगेड को क्या अंतर्राष्ट्रीय जगत में यह सन्देश नहीं देना चाहिए था कि धारा 370 की वजह से कश्मीर की सबसे दबी व पिछड़ी जनता के हकों के साथ समझौता किया गया था और उन्हें सदियों पुरानी सामाजिक व्यवस्था के दायरे में मजबूर किया गया था।

जरूरत इस बात की थी कि प्रत्येक दल और विचारधारा के भारतीय एक स्वर से कहते कि पाकिस्तान द्वारा जबरन कब्जाये कश्मीर को वापस लिया जाये और उसमें रहने वाले लोगों को भी अधिकार सम्पन्न किया जाये, परन्तु ये लोग उलटा राग ही अलाप रहे हैं और भारत के विरोधी पाकिस्तान के हाथ में औजार पकड़ा रहे हैं। क्या भारत से ये समवेत स्वर नहीं उठने चाहिएं कि पाकिस्तान की पीठ थपथपाते हुए पड़ौसी देश चीन जिस तरह कब्जाये गये कश्मीर में विभिन्न परियोजनाएं चला रहा है वह नाजायज है क्योंकि 26 अक्टूबर 1947 को जिस जम्मू–कश्मीर का विलय भारतीय संघ में किया गया था वह उसी का हिस्सा था। इससे पहले जम्मू–कशमीर व पाकिस्तान के बीच क्या हुआ उसका अस्तित्व 26 अक्टूबर को ही समाप्त हो गया था और पाकिस्तान की हैसियत एक हमलावर मुल्क की हो गई थी।

अतः भारत के विदेश मन्त्रालय ने इस बारे में स्पष्ट करते हुए भारत का रुख खोल दिया है। कयामत तो ये है कि मानवाधिकारों के नाम पर इंसानियत का झंडा उठाये ये लोग इस कदर बदगुमानी में रहते हैं कि वे यह तक भूल जाते हैं कि वजूद में आने के बाद पाकिस्तान की फौज दुनिया की अकेली जालिमाना फौज है जिसने पूर्वी पाकिस्तान में 1971 में अपने ही देश के मुस्लिम नागरिकों का कत्लेआम किया था और लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था। इनमें 95 प्रतिशत से ज्यादा मुसलमान नागरिक ही थे। हमें आज केवल यह देखना है कि समूचा जम्मू–कश्मीर भारत का अंग बने, पाकिस्तान की जालिमाना हरकतें उसके अपने देश के बलूचियों व सिन्धियों पर भी बन्द हों।

देश पर 600 साल शासन करने वाला मुस्लिम समाज भयभीत क्यों है : आरएसएस

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संयुक्त महासचिव कृष्ण गोपाल ने दिल्ली मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र और विचारक दारा शिकोह पर आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दारा शिकोह ने भारत पर शासन किया होता तो इस्लाम देश में पनपता और हिंदू भी इस्लाम को बेहतर तरीके से समझ पाते। कृष्ण गोपाल ने देश में सभी धर्मों के बीच समन्वय की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश पर 600 साल तक शासन करने वाला और 16–17 करोड़ की आबादी वाला मुस्लिम समाज भयभीत क्यों है जबकि कुछ लाख एवं हजार की आबादी वाले अन्य धर्मों के लोग भयभीत नहीं हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भय है तो उसे दूसरे करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। गोपाल ने यह भी कहा कि भारत में यह कोई नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी दुखी रहें क्योंकि भारत की परंपरा सर्व भवंतु सुखिनः की है। उन्होंने एक लेख का हवाला देते हुए कहा कि देश में पारसी करीब 50 हजार हैं, जैन 45 लाख हैं, बौद्ध 80–90 लाख हैं, यहूदी पांच हजार हैं। ये लोग भयभीत नहीं है। आपने कभी सुना है कि पारसी भयभीत है, जैन भयभीत हैं? तुम 16–17 करोड़ लोग हो, तुम भयभीत क्यों हैं, किससे भयभीत हो? यह बड़ा प्रश्न है।

आरएसएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि जिस समाज ने 600 वर्षों तक शासन किया हो वो भयभीत क्यों हो गया और किससे भयभीत हो गया? उन्होंने कहा कि हमारे समाज ने सभी लोगों को अपनाया और सभी को अपने घर में प्रेम से रखा है। अगर आप समन्वय के धागे ढूंढेंगे तो समन्वय के धागे मिलेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस देश ने कभी किसी विभाजनकारी नीति और सोच को प्रश्रय नहीं दिया। सारी धरती अपनी है। सर्वे भवंतु सुखिनरू, यह हमारी परंपरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से रोज झंझट चलता है। अगर कोई नया मंत्र बनाए कि पाकिस्तान को छोड़कर सभी खुश रहें, तो पक्का मानिए कि इस देश के लोग यह स्वीकार नहीं करेंगे। पाकिस्तान भी दुखी क्यों रहे? पाकिस्तान के लोग भी सुखी रहें? भारत की सोच विभाजनकारी नहीं है। दाराशिकोह को लेकर गोपाल ने कहा कि औरंगजेब क्रूरता का प्रतीक था तो दारा शिकोह समावेशी सोच के प्रतीक थे।

अलकायदा सरगना ने कहा

अमेरिका, यूरोप, रूस को अब तबाह कर दो

नई दिल्ली। आतंकी संगठन अलकायदा के सरगना अयमान अल–जवाहिरी ने 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर वीडियो जारी कर मुस्लिमों को पश्चिमी देशों पर हमला करने के लिए उकसाया है। वीडियो में जवाहिरी मुस्लिमों से कह रहा है कि अमेरिका, यूरोप, इसराइल और रूस जैसे पश्चिमी देशों पर हमला करके उन्हें बर्बाद कर दें। अल–जवाहिरी 9ध्11 आतंकी हमले की 18वीं बरसी पर मुस्लिमों को संबोधित कर रहा था। अमेरिकी कंपनी सर्च फॉर इंटरनेशनल टेररिस्ट एटिटीज (एसआईटीई) ने इसका खुलासा किया है। एसआईटीई आतंकी संगठनों की ऑनलाइन गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए जानी जाती है। इसके बाद ही जवाहिरी का यह वीडियो सामने आया है। वीडियो में आतंकी सरगना ने कहा कि यदि आप जिहाद चाहते हैं, तो पश्चिमी देशों की सेना को धीरे–धीरे खत्म करते रहें। अमेरिकी सैनिक आज पूर्व से पश्चिम तक पूरी दुनिया में हैं। उसने लोगों को भड़काते हुए कहा कि आपके देश के भीतर अमेरिकी ठिकानों भरे हुए हैं, जिसमें सभी काफिर हैं। उनके द्वारा भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। जवाहिरी का यह भाषण 33 मिनट 28 सेकंड का है। वीडियो को अलकायदा के ही अस–सहाब मीडिया फाउंडेशन ने जारी किया है। जवाहिरी ने अपने भाषण में जिहादी रास्ता छोड़ने वाले लोगों की आलोचना करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि 9ध्11 जैसे हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि इनमें निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान के काबुल में अमेरिकी दूतावास के पास धमाका हुआ था। अभी तक किसी संगठन ने धमाके की जिम्मेदारी नहीं ली है। बताया गया है कि यह एक तरह का रॉकेट ब्लास्ट था। बता दें कि 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन पर हुए हमले में 2983 लोग मारे गए थे। इसके पीछे अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन का हाथ था। जिसके बाद अमेरिका ने मई 2011 में लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में घुस कर मार गिराया था। अल–जवाहिरी 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद संगठन प्रमुख बना था। जवाहिरी मिस्त्र का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, जवाहिरी अभी पाकिस्तान या अफगानिस्तान में छिपा हो सकता है।

इमरान को लगा झटका

इस्लामाबाद। मोदी सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से धारा 370 के कुछ प्रावधानों को निरस्त किए जाने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान विश्व के हर एक प्लेटफॉर्म पर कश्मीर राग अलाप रहे हैं और उनकी बात कोई मानने के लिए तैयार भी नहीं है। ऐसे में अब इमरान खान को एक और झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान के गृहमंत्री एजाज अहमद शाह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी ने पाकिस्तान की छवि इतनी ज्यादा बर्बाद कर दी कि हमें कोई गंभीरता से ले ही नहीं रहा। गृह मंत्री इतने में ही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मामले में वैश्विक समर्थन पाने में नाकाम रहा है। उन्होंने आगे पाकिस्तान की छवि खराब करने के लिए बेनजरी भुट्टो, परवेज मुशर्रफ और इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया। गृह मंत्री शाह ने कहा कि लोग हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि भारत ने जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगाया हुआ है और वहां के लोगों को दवाईयां तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं।